IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

शिक्षा में कौशल विकास की भूमिका का विश्लेषणात्मक अध्ययन

मो0 फैसल ईसा*

डा0 सरोज यादव**

*शोध छात्र,(जे0आर0एफ0), शिक्षाशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज,

**असि0 प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज,

शोध सारांश

'हर हाथ को हुनर हर हाथ को रोजगार' किसी भी देश के लिए इससे ज्यादा सम्मानजनक स्थिति क्या हो सकती है। शिक्षा मानव के विकास और रोजगार के लिए ही जरूरी नहीं है बल्कि वह देश के निर्माण के लिए भी महत्वपूर्ण है। कौशल और ज्ञान देश के लिए आर्थिक प्रगति और सामाजिक विकास की प्रेरक शक्तियां हैं। विभिन्न प्रकार के कौशल आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था के संचालक के रूप में कार्य करते हैं। इनसाइक्लोपीडिया अमेरिका के अनुसार–"किसी व्यावसाय के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल एवं अभिवृत्तियों की शिक्षा देना तकनीकी या व्यावसायिक शिक्षा है।" व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत वह सभी प्रकार की शिक्षा सम्मिलित हैं जिसके द्वारा मानव को जीविकोपार्जन के लिए प्रशिक्षण प्राप्त होता है। व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण का उद्देश्य मनुष्य की रोजगार क्षमता में वृद्धि करना है। निःसन्देह शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है, परन्तु व्यावसायिक शिक्षा के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है, जो कि भारत के विकास के लिए एक आवश्यक स्तम्भ है।

कुंजी शब्द : शिक्षा, कौशल, रोजगार।

प्रस्तावना :

कौशल और ज्ञान, किसी भी देश के लिए आर्थिक प्रगति और सामाजिक विकास की प्रेरक शक्तियां होती हैं। कौशल स्तर के उच्च और बेहतर मानक वाले देश, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय जॉब मार्केट में चुनौतियों और अवसरों को अधिक प्रभावशाली ढंग से समायोजित करते हैं। भारत में शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण की स्थिति पर एनएसएसओ, 2011–12 (68वें दौर) रिपोर्ट के अनुसार 15 से 59 वर्ष की आयु के व्यक्तियों में से औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों की संख्या लगभग 2.2 प्रतिशत तथा गैर–औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों की संख्या 8.6 प्रतिशत बताई गई है। हालांकि चुनौतियों केवास्तविक परिमाप पर बहस होती रहती है, किंतु यह निर्विवाद तथ्य है कि चुनौती बहुत बड़ी है। आजादी के बाद भारत में बुनियादी शिक्षा की दिशा में तेजी से प्रयास हुए लेकिन व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया, यही कारण है कि वर्ष 2011 की जनगणना में देश की साक्षरता दर 74 प्रतिशत तक पहुँच गयी लेकिन औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास का स्तर काफी निम्न रहा। वास्तव में आज हमारे देश में 5 प्रतिशत लोग भी ऐसे नहीं है जिन्होंने औपचारिक रूप से श्रम बल कौशल या व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करे तो यहाँ की स्थिति और भी निराशाजनक है। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जर्मनी, चीन और दक्षिण कोरिया जैसे उन्नतशील अर्थव्यवस्थाओं में व्यावसायिक शिक्षा में नामांकन का स्तर भारत की तुलना में काफी उच्चतम है। वास्तव में किसी भी समाज की तरक्की का सीधा सम्बन्ध वहाँ के कौशल विकास के स्तर से होता है। जिन देशों में कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा का स्तर उच्च है वहाँ पर आर्थिक और मानव विकास का भी स्तर ऊँचा है। अतः देश के विकास विशेषतः ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा पर काफी जोर देने की आवश्यकता है। भारत के ग्रामीण क्षेत्र में अगर कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण के स्तर को ऊपर उठता हुआ देखना है तो शिक्षा तथा संसाधन को उन्नत बनाने के साथ ही साथ विषमताओं को भी दूर करना होगा।

कौशल विकास का उद्देश्य :

राष्ट्र के ज्यादा से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगाार परक बनाने एवं विकास के नये क्षेत्र ढूंढना और उन्हें विकसित करना कौशल विकास के मुख्य उद्देश्य हैं। इसके अन्य उद्देश्य निम्न है–

- आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी जो उचित शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उनके अर्न्तनिहित कौशलों की पहचान करना।
- अधिक से अधिक युवाओं के कौशलों को पहचान कर उन्हें उनकी अभिरूचि, अभिक्षमता तथा योग्यता के अनुसार रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
- युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगाार योग्य बनाने और अपनी जीविका सुनिश्चित करने में सक्षम बनाना एवं प्रोत्साहित करना।
- भारतीय बेरेजगार युवकों एवं युवतियों को रोजगार परक बनाकर राष्ट्र की प्रगति में सम्मिलित करना।
- युवाओं को व्यावसायिक शिक्षा के साथ–साथ कम्प्यूटर आधारित शिक्षा प्रदान करना।

वर्तमान परिदृश्य में कौशल विकास एवं व्यावसायिक शिक्षा की दशा :

वर्तमान सरकार ने कौशल विकास को प्राथमिकता देते हुए देश में एक अलग कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की स्थापना की है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने सन् 2015 में कौशल विकास योजना भी शुरू की है। योजना समिति की रिपोर्ट के अनुसार इस योजना के अन्तर्गत 2.5 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इस योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी के जरिए विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से बल दिया जा रहा है। सरकार ने कौशल विकास को औपचारिक शिक्षा से जोड़ने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की तर्ज पर देश में पहले भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना कानपुर में की है। इस संस्थान की अवधारणा सिंगापुर के तकनीकी शिक्षा संस्थान के आधार पर तैयार की गई है। सरकार ने भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाने का विज़न रखा है। व्यावसायिक शिक्षा की स्थिति पिछले कुछ वर्षों में बेहतर दिख रही है। देश में व्यावसायिक शिक्षा देने वाले विद्यालयों की संख्या 2014–15 में 960 थी जबकि 2021–22 में यह संख्या बढ़कर 11710 हो गयी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह वर्णित किया गया है कि–शिक्षा का उद्देश्य संज्ञानात्मक विकास के साथ–साथ चरित्र निर्माण एवं 21वीं सदी के प्रमुख कौशल से युक्त एवं बहुमुखी प्रतिभा वाले व्यक्तियों का निर्माण करना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक उद्देश्य यह भी वर्णित किया गया है कि 2025 तक विद्यालय और उच्च शिक्षा के माध्यम से कम से कम 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी।

कुशल भारत मिशन –

कुशल भारत मिशन के तहत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) देश भर में प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों/स्कीमों को कार्यान्वित कर रहा है। एमएसडीई के कार्यक्रमों के तहत देश भर में प्रचालनरत कौशल विकास केंद्रों की संख्या नीचे दी गई है –

(1) कार्यक्रम/स्कीम देश भर में प्रचालनरत प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के तहत प्रशिक्षण केंद्र (टीसी) (प्रधानमंत्री कौशल केंद्र (पीएमकेके) सहित) 1,484, जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) (नव स्वीकृत सहित) 309 और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) 14,716।

(2) कौशलीकरण की वर्तमान मांग को पूरा करने के लिए, एमएसडीई न देश के प्रत्येक जिले में 'प्रधानमत्री कौशल केंद्र (पीएमकेके)' नामक आदर्श आकांक्षात्मक कौशल केंद्र की स्थापना की दिशा में पहल की है। इस पहल के तहत अब तक 717 पीएमकके स्थापित किए जा चुके है। इसके अतिरिक्त, 14,711 आई0टी0आई0 प्रशिक्षण केन्द्रों और 309 जेएसएस प्रशिक्षण केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है।

राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन –

राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (एनएसडीएम), 15 जुलाई, 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर माननीय प्रधान मंत्री द्वारा शुरू किया गया था। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन देश में कौशलीकरण गतिविधियों का कार्यान्वयन करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच एक सुदृढ़ संस्थागत ढांचा प्रदान करने के लिए है। इस मिशन में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाली तीन स्तरीय संरचना है। समग्र मार्गदर्शन और नीति–निर्देश प्रदान करने के लिए इसके शीर्ष स्तर पर, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मिशन की सचांलन परिषद है। कौशल विकास के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में संचालन समिति, संचालन परिषद द्वारा निर्धारित दिशा के अनुरूप मिशन की गतिविधियों की समीक्षा करती है। मिशन निदेशालय के मिशन निदेशक के रूप में सचिव, कौशल विकास केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों में कौशल गतिविधियों का कार्यान्वयन, समन्वय और अभिसरण सुनिश्चित कराते हैं। उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में मिशन के चुनिन्दा उप–मिशन भी हैं। मिशन के समग्र उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रारंभ में सात उप–मिशनों को ढांचे के रूप में कार्य करने का प्रस्ताव दिया गया है। ये निम्नलिखित हैं: (1) संस्थागत प्रशिक्षण, (2) अवसंरचना, (3) अभिसरण, (4) प्रशिक्षक, (5) विदेशी रोजगार, (6) सतत आजीविका, (7) सार्वजनिक अवसंरचना का लाभ उठाना।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) –

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अनुरूप) के अतंर्गत 2009 में वित्त मत्रांलय, भारत द्वारा स्थापित एक सार्वजनिक निजी भागीदारी फर्म है। कौशल विकास में निजी क्षेत्र की पहल के समन्वय/प्रेरित करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 मई 2008 को पीपीपी

निकाय के रूप में इसे मंजूरी दी थी। बाजार की जरूरतों से प्रेरित और विश्व स्तर के कौशल प्रदान करने वाले "निजी क्षेत्र के नेतृत्व करने वाले" के रूप में इसकी कल्पना की गई थी। एनएसडीसी भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) के साथ मिलकर काम करता है। इसका एमएसडीई के अंतर्गत एक ट्रस्ट, राष्ट्रीय कौशल विकास कोष (एनएसडीएफ) के साथ एक निवेश प्रबंधन समझौता है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना –

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) को 2015 में प्रायोगिक स्कीम के रूप में शुरू किया गया था ताकि देश में कौशल विकास को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क अल्पावधि कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किया जा सके और युवाओं को कौशल प्रमाणन प्राप्त करने के लिए मौद्रिक पुरस्कार प्रदान करके इसे प्रोत्साहित किया जा सके। इसके प्रायोगिक चरण के दौरान, देश भर में लगभग 19.85 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित/उन्मुख किया गया है। इसके कार्यान्वयन के प्रथम वर्ष के सफल होने के कारण, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएमकेवीवाई 2.0 (2016–20) के अंतर्गत 12,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से देश के 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए स्कीम को और चार वर्ष के लिए मंजूरी दी थी। 31.10.2021 तक, देश भर में लगभग 109 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित/उन्मुख किया गया है। प्रमुख स्कीम का तृतीय चरण– प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (यानी पीएमकेवीवाई 3.0) जनवरी 2021 में शुरू की गई है। पीएमकेवीवाई 1.0 और पीएमकेवीवाई 2.0 के अनुभवों को शामिल करते हुए, पीएमकेवीवाई 3.0 का शुभारंभ किया गया है, जिसमें जिला स्तर पर कौशल अंतराल को दूर करने और मांग का आकलन करने के लिए दिशानिर्देशों की सुदृढ़ श्रेणी की साक्षी जिला कौशल समितियों (डीएससी) की बढ़ती भूमिका नजर आ रही है। 31.10.2021 तक, पूरे देश में 2.52 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित/उन्मुख किया गया है।

कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा की चुनौतियाँ–

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) की रिपोर्ट–2021 से ज्ञात होता है कि विश्व की आबादी 779 करोड़ है जिसमें से युवा 121 करोड़ है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की वर्ल्ड एम्पलॉयमेन्ट एण्ड सोशल आउटलुक ट्रेण्ड–2022 के अनुसार भारत की आबादी 138 करोड़ है जिसमें 25 करोड़ युवा हैं। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की वर्ल्ड एम्पलॉयमेन्ट एण्ड सोशल आउटलुक ट्रेण्ड–2022 के अनुसार 2021 में बेरोजगारी का ऑकड़ा–21.4 करोड़ है। इस स्थिति को कम करने का एक तरीका इन युवाओं का कौशल विकास ही है। सेन्टर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) के अनुसार भारत में बेरोजगारी की दर अगस्त–2022 में 8.3 प्रतिशत है जो कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) वर्ष 2021 में 6.6 प्रतिशत की वैश्विक बेरोजगारी दर से अधिक है।

उपरोक्त ऑकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत में युवा बेरोजगारी अधिक है। इस बेरोजगारी को दूर करने का एक ही उपाय है कि इन युवाओं को कौशल विकास एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करके आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है और बेरोजगारी दर को कम किया जा सकता है। कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने में निम्न चुनौतियां है–

- उच्च शिक्षा स्तर पर तकनीकी विषयों के स्थान पर कला, वाणिज्य एवं विज्ञान जैसे विषयों पर अधिक बल दिया जाता है।
- अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की वर्ल्ड एम्पलॉयमेन्ट एण्ड सोशल आउटलुक ट्रेण्ड–2022 के अनुसार 2021 में बेरोजगारी का ऑकड़ा–21.4 करोड़ है, इतनी बड़ी जनसंख्या को प्रशिक्षित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।
- कुशल प्रशिक्षकों की आवश्यकता।
- तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों एवं व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों की कमी।
- वर्तमान समय की आवश्यकता को देखते हुए उचित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का न होना।

कौशल विकास एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए आवश्यक सुझाव–

1– विद्यार्थियों को उचित मार्गदर्शन प्रदान करना जिसके माध्यम से वे सही व्यावसायिक पाठ्यक्रम का चयन कर सकें।

2– कौशल विकास मिशन संस्थान एवं आई0टी0आई0, पॉलिटेक्निक, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार खोलने का प्रयास करना।

3– उच्च शिक्षा संस्थानों को सॉफ्ट स्किल सहित विभिन्न कौशलों में अल्पावधि प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति दी जाऐ जिनकी वर्तमान समय में अत्यधिक मांग हो।

4– विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में परिवर्तन करना, और प्रशिक्षण संस्थानों या व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों में लागू करना।

5– कौशल विकास मिशन संस्थान एवं व्यावसायिक शिक्षा संस्थान में योग्य एवं कुशल प्रशिक्षकों की नियुक्ति करना।

निष्कर्ष –

शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, इसलिए शिक्षा का उपयोग सामाजिक विकास के साधन के रूप में किया जाता है। यह राष्ट्रीय एकता एवं विकास को बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाती है। इसके द्वारा सामाजिक कुशलता का विकास होता है। यह समाज को कुशल कार्यकर्ताओं की पूर्ति करती है। यह समाज की सभ्यता एवं संस्कृति का संरक्षण, पोषण एवं उसका प्रसार करती है। यह समाज के लिए योग्य नागरिकों का निर्माण करती है। शिक्षा सामाजिक सुधार एवं उन्नति में सहायक होती है। उचित शिक्षा के अभाव में मनुष्य कार्यकुशल नहीं बन सकता। कार्यकुशलता के बिना व्यावसायिक एवं आर्थिक सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। एक राष्ट्र तभी विकास कर सकता है जब उस राष्ट्र के युवा कुशल हों और उन्हें उनकी कुशलता के अनुरूप रोजगार भी प्राप्त हो। इसी उद्देश्य से कौशल विकास योजना की रूपरेखा तैयार की गयी थी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. मिश्रा, आर0 (2002). विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की अभिक्षमता, व्यावसायिक अभिरूचि एवं उपलब्धि का अध्ययन्, अप्रकाशित शोध प्रबन्ध, इलाहाबादः इलाहाबाद विश्वविद्यालय।
2. राव, आर0 एवं प्रकाश पी0. (2021), भविष्य के लिए कौशल विकास, *कुरूक्षेत्र मासिक पत्रिका* (अंक 2), दिसम्बर 2021, पृ0सं0 05–12।
3. यादव, एस0. (2022). युवाओं का कौशल विकास, *योजना मासिक पत्रिका* (अंक 02), फरवरी 2022, पृ0सं0 19–22।
4. सिंह, ए0, के0. (2009). मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियाँ, दिल्लीः मोतीलाल, बनारसीदास।
5. सिंह, एस0 (2016). कौशल विकास, दिल्ली : अग्नि प्रकाशन।